>

Title: Need to address the problems being faced by the Monitors working under National Polio Eradication Scheme.

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): माननीय महोदय, आपको धन्यवाद देने के साथ-साथ मैं आपके माध्यम से भारत सरकार एवं डब्लू.एच.ओ. द्वारा बनाये गये संयुक्त उपक्रम राष्ट्रीय पोलियो निरीक्षण योजना (एन.पी.एस.पी.) के अन्तर्गत मानीटरों की संविदा पर नियुक्ति की गई थी। उत्तर प्रदेश में 580 और पूरे देश में 1500 मानीटर कार्यरत हैं। इन्हीं मानीटरों की 10 वर्षों की मेहनत और लगन का परिणाम है कि वर्ष 2012 में हमारे भारत देश को पोलियोमुक्त राष्ट्र घोषित किया गया है। पल्स पोलियो का माइक्रोप्लान बनाने से लेकर, वैक्सीनेटरों को प्रशिक्षण देने एवं इस अभियान की मानीटरिंग करने की जिम्मेदारी इन मानीटरों को दी गई थी। ठंडी, गर्मी, बरसात में हर तरह से कष्ट सहते हुए ये लोग काम पूरा करते हैं। आज के महंगाई के दौर में ऐसे जिम्मेदारीपूर्ण कार्य हेतु मानीटरों को केवल 11960 रुपये दिये जाते हैं। वर्ष 2003 में जब पैट्रोल का दाम 25 रुपये प्रति लीटर था...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कहा था कि संक्षेप में बोलें।

डॉ. संजय सिंह : तब इन्हें पैट्रोल खर्च का केवल 2500 रुपये दिया जाता था, आज पैट्रोल का दाम तीन गुना बढ़ गया है, फिर भी इन्हें 3000 रुपये प्रदान किया जा रहा है।

चेचक के उन्मूलन के लिए पूर्व में ऐसा ही अभियान चलाया गया था और उस कार्य में लगे मानीटरों को एस.सी. पी. के पद सृजित कर समायोजित कर दिया गया था। पल्स पोलियो अभियान में लगे मानीटरों को भी सरकार से कुछ ऐसी ही उम्मीद थी...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपका सरकार से क्या मांगना है, वह बता दीजिए न।

डॉ. संजय सिंह : किन्तु डब्लू.एच.ओ. द्वारा इस परियोजना में कार्यरत मानीटरों को कार्यमुक्त करते हुए आवश्यकतानुसार नये पद सृजित कर इंटरव्यू के माध्यम से संविदा पर नियुक्त करने की योजना है। आपसे निवेदन है कि इस काम में 10 वर्षों से कार्यरत मोनीटरों को उत्कृष्ट कार्य करने की जगह उपकृत करने की बजाय उनकी रोजी-रोटी की भी समस्या सामने आ रही है। सदन के माध्यम से आप से अनुरोध है कि पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम में कार्यरत सभी मानीटरों को स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किया जाये, विशेष परिस्थितियों में यदि यह सम्भव न हो तो राष्ट्रीय पोलियो निरीक्षण योजना के संचालन तक इन्हें उनके पद पर बने रहने दिया जाये। मानीटरों का मानदेय बढ़ाकर समान पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के बराबर किया जाये। पैट्रोल/डीजल खर्च पर 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाये और एन.पी.एस.सी. के कर्मचारियों/अधिकारियों की भांति मानीटरों को भी अवकाश/स्वास्थ्य लाभ की सुविधा प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें। यह तो पूरा का पूरा दो पेज का मैटर आप पढ़ गये। बहुत लम्बा नहीं, संक्षेप में बोलिये।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, विषय रखिये और बताइये कि आप सरकार से क्या चाहते हैं।